(b) the number and the capacity of the units that have come up on these Letters of Intent ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAHNAWAZ KHAN) : (a) and (b). During 1970-71, only one Letter of Intent was issued for the production of Cold Rolled Strips. This was granted to M/s. Andhra Steel Corporation Limited, Calcutta, for setting up an industrial undertaking at Hyderbad for the manufacture of 7,000 tonnes cold rolled narrow strips and 3,000 tonnes of box strappings per annum. It was converted into an Industrial Licence on 23.11.71 and issued in favour of M/s. Southern Steel Limited, Calcutta, a new Company floated for implementing the scheme. It is reported that the factory has been set up.

Production of wire Roads by M/s Electro Steel casting

3421. SHRI C. CHITTIBABU : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the encouragement given to the setting up of new units for the production of wire rods particularly of high carbon and other special categories ;

(b) the capacity that has been created ;

(c) whether M/s Electro Steel Casting has created the capacity to produce 40,000 tonnes of wire rods per annum and if so the particulars of production so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAHNAWAZ KHAN) : (a). No particular assistance is being given for production of wire rods, as a substantial capacity already exists in the country.

(b) The present available capacity for rolling mild steel and high carbon steel wire rods in the country is estimated to be of the order of 900,000 tonnes per annum.

(c) No, Sir. The letter of Intent granted to M/s. Electro-Steel Castings for the production of 40,000 tonnes of wire rods has not been implemented as yet.

राजस्थान के पहाड़ों के खनिजों के बारे में सर्वेक्षण

3422. **श्री लाल जी भाई** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में उदयपुर में तथा अन्य जिलों में ऐसे पहाड़ है जिनमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहा सर्वेक्षण करने का सरकार का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहले ही राजस्थान के उदयपुर और अन्य जिलों के पहाड़ी भूभागों में भूवैज्ञानिक मानचित्रण और सर्वेक्षण किए है। इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप उदयपुर जिले के पहाड़ी भूभागों मे सीमा, जिंक फास्फोराइट, लौह अयस्क के निक्षेप और बेरियल, पन्ना, अभ्रक, स्टीटाइट, मैंगनीज और भवन सामग्री के प्राप्ति स्थल पहले ही अवस्थापित किए गए हैं। राजस्थान के अजमेर, अलवर, बन्सवारा, भीलवाड़ा, भरतपुर, बुन्दी, चित्तौड़गढ़, धुगरपुर, सवाई माधोपुर, सिकार, सिरोही और टोक जिलों के पहाड़ी भूभागों में एस्बस्टोस, बेराइट, बेरियल, भवन सामग्री, पन्ना, पेल्डस्पार, पलोमपार, काच रेत, लौह अयस्क, काइनाइट, काओलिन, सीसा जस्ता और ताम्र अयस्क और चूना पत्थर, अभ्रक, पाइराइट के प्राप्ति स्थल भी अवस्थापित किए गए है। इन जिलों मे अतिरिक्त भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए जा रहे है।

Ayurvedic Dispensaries run by Coal Mines Labour Welfare Organisation

3423. SHRI SHRIKISHAN MODI : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the Coal Mines Labour Welfare Organisation is running 30 Ayurvedic Dispensaries in the coal fields of some States ;

(b) whether Government helps them in running these dispensaries, if so, to what extent ; and

(c) whether Government propose to give free medical facilities to the coal and mine labourers throughout the country, if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) The Coal Mines Labour Welfare Organisation, Dhanbad, is running 29 Ayurvedic *Dispensaries* and one Ayurvedic Pharmacy for the benefit of coal miners in the States of Assam, Andhra Pradesh, Bihar Orissa, Madhya Pradesh and West Bengal.

(b) The entire cost of running these Ayurvedic Dispensaries is met out of the Coal Mines Labour Welfare Fund.

(c) At present all colliery workers drawing basic pay upto Rs. 500/-p. m. and their dependents in all coal-fields are being given free medical facilities.

गया जिला (बिहार) में खनिजों के बारे में सर्वेक्षण

3425. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया जिला बिहार के पहाड़ों मे अनेक खनिज पाये जाने की सम्भावनाएं है ;

(ख) यदि हा, तो क्या सरकार इस बारे मे कोई सर्वेक्षण करायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नही, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पहले ही किए गए भूवैज्ञानिक अन्वेषणों के परिणामस्वरूप बिहार के गया जिले के पहाड़ी भूभागों में अभ्रक के कार्ययोग्य निक्षेप अवस्थापित किए गए है। इस क्षेत्र में ओचे, टिन अयस्क, पिटचब्लेन्डे और कोलुम्बाइट—टेन्टालाइट के लघु प्राप्ति स्थल भी अभिलिखित किए गए है।

(ख) और (ग). इस क्षेत्र में व्यवस्थित मानचित्रण और खनिज अन्वेषणों का आगे का कार्य प्रगति पर है।

बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये विदेशी सहायता का प्रयोग किया जाना

3426. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से प्राप्त कुल सहायता का कितने प्रतिशत भाग बंगला देश से आये शरणार्थियों पर व्यय किया गया है ; और

(ख) सरकार का विचार शेष राशि को किन मदों पर व्यय करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). बंगला देश के शरणार्थियो पर किए जाने वाले लगभग 325 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च मे से भारत सरकार को विदेशो, अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों आदि मे, नकद और सामान के रूप में, अब तक केवल 136.77 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। चूकि प्राप्त की गई राशि किए गए खर्च से बहुत कम है, इसलिए शेष राशि को अन्य मदों पर खर्च करने का प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में खुदरा विक्रेताओं को कोयले का वितरण

3427. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या इस्पात और खान मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कोयले के खुदरा व्यापारियों को कोयला का उतना कोटा नहीं दिया जाता है जितने कोटे की वे माग करते हैं ;

(ख) खुदरा व्यापारियों के लिये कोयले का कोटा नियत करने सम्बन्धी नियम क्या हैं; और

(ग) सरकार के पास खुदरा व्यापारियों के ऐसे कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं और सरकार द्वारा उन पर निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं ?